exchanges were set up during 2004-05 and how many WLL Exchanges were set up during 2004-05 in Assam and the North-Eastern region?

MR. CHAIRMAN: I think, this is out of scope of this question.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Next Question.

*585[The questioner (Shri Pyare Lal Khandelwal) was absent for answer *vide* page 45 *infra*.]

Loans given by KVIC

*586. SHRI R.K. ANAND: Will the Minister of AGRO AND RURAL INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that KVIC continued to release rebate claim and extend financial assistance to the tune of about Rs. 4 crores as loan to institutions in violation of its own rules; and

(b) the steps taken by Government for the protection of artisans rights?

THE MINISTER OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES (SHRI MAHABIR PRASAD): (a) and (b) A Statement is placed on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The Khadi Certification Rules and the Khadi Certification Code, 2003 provide for the creation of Artisan Welfare Fund (AWF) at the level of each institution registered with the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) for the welfare of the self-employed artisans who supply khadi articles to the institution. Artisans' subscriptions and matching contributions of the institutions at such rates as may be prescribed by the Central Certification Committee or the KVIC or its authorised officers are deposited into the AWF. In case of default in this respect by an institution, various corrective measures have been provided for, which include not paying the rebate amounts to the institutions concerned.

However, the KVIC has released the rebate amounts to the Khadi institutions which did not fully comply with the above-mentioned provisions regarding the AWF. The rebate amounts were released to these Khadi

institutions to enable them to buy and supply necessary raw materials to the Khadi, artisans, buy yarn and supply it to the artisans (weavers) and pay wages to the artisans. If the rebate amounts were not released to these institutions, the difficulties of the artisans on account of loss of employment and wages would have increased further. The KVIC has, however, stopped providing financial assistance in the form of loan to its registered institutions since 1997-98.

(b) As a measure of providing social security to the khadi artisans, Janashree Bima Yojana (JBY) has been launched with effect from 15 August, 2003 to cover 3.9 lakh artisans during the remaining period of the 10th Plan. The scheme provides for insurance coverage against death and disability to khadi artisans. 2.03 lakh artisans have been covered under this scheme up to 31 January, 2005.

SHRI R.K. ANAND: Mr. Chairman, Sir, for the benefit of artisans, the codified rules lay down the creation of Artisan Welfare Fund which consists of 10 per cent of the artisan wages and an equal matching by the institutions employing them. This is to be deposited in nationalised banks. I would like to know from the hon. Minister as to how many institutions are not depositing this amount collected from the employees and the matching contribution by them in the bank.

श्री महावीर प्रसाद: सभापति जी, माननीय सदस्य ने ऐसा प्रश्न किया है जो कामगारों से संबंधित है। कामगारों से संबंधित एक कल्याण निधि बनाई गई है। जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं उन्हें आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा कुल बीस सौ चौबीस खादी संस्थानों को वर्ष 1997-98 से पूर्व 513.17 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था। इन संस्थानों में से लगभग दो सौ संस्थाएं ऐसी हैं, जिन पर एक करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण है। इस तरह से संपूर्ण संस्थाओं में से कुछ संस्थाएं जिन पर एक करोड़ से ज्यादा का ऋण बकाया है, इन्होंने अभी तक पैसा जमा नहीं किया गया है। इसमें दस प्रतिशत कामगार का हिस्सा होता है, 10 प्रतिशत संस्थाओं का हिस्सा होता है, इस तरह से कल्याण समिति बनाई जाती है, जो कामगारों के हित के लिए होती है। हम उनसे बार-बार बकाए के लिए आग्रह कर रहे हैं। चूंकि खादी एक ऐसी संस्था है, यदि हम उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, तो इससे हजारों, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए हम सुधारात्मक कार्रवाई करके उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि उनका जो बकाया पैसा है, वह जल्द से जल्द जमा करा दें। उन्हें सितम्बर, 2005 तक जमा करने को निर्गत किया गया है।

श्री सभापति: आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, he is satisfied.

SHRI R K. ANAND: Yes; Sir, I am satisfied.

श्री राजू परमार: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गुजरात में जो वीवर्स रजिस्टर्ड को-ऑपरेटिव सोसायटीज हैं, उनमें से कई सोसायटीज को रिबेट नहीं दी जा रही है। वहां पर जो अच्छी सोसायटीज काम कर रही हैं, उन्हें रिबेट नहीं मिल रहा है, साथ ही वहां की गुजरात सरकार की ओर से उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया गया है। क्या आपको ऐसी कोई जानकारी है? यदि जानकारी है तो उसका ब्यौरा आप हमें दे दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद: सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम साल भर तक दस प्रतिशत रिबेट देते हैं। यह के० वी० आई० सी० देती है। गांधी जयंती के बाद 108 दिन की बीस प्रतिशत रिबेट दी जाती है। इस तरह से के० वी० आई० सी० के पास लगभग सात करोड़ रिबेट अभी बाकी है, अन्य राज्यों में लगभग छप्पन करोड़ रिबेट बाकी है। सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कुछ तकनीकी आधार पर, क्योंकि भारत सरकार के पास, के० वी० आई० सी० के पास, रिबेट देने के लिए हमारे पास काफी पैसा है, यदि तकनीकी आधार पर, ऑडिट के आधार पर हमारे पास तथ्यात्मक विचार आता है, तो हम उसे पुन: रिबेट दे देते हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने गुजरात का प्रश्न पूछा है, मैं इसकी जानकारी उन्हें अलग से दे दूंगा।

श्री मोती लाल वोरा: सभापति जी, 513 संस्थाएं हैं, जिन्हें उन्होंने कामगारों के हितों के लिए रिबेट दी थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस रिबेट को दिए जाने के बाद खादी के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? रिबेट देने का मतलब है कि कामगारों को वहां बराबर काम मिले और खादी के उत्पादन में वृद्धि हो। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन 513 संस्थाओं को, जिन्हें आपने दस प्रतिशत की रिबेट दी है, इससे खादी के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है?

श्री सभापति: अभी इस समय वे क्या जवाब देंगे? अगर आप जवाब देने वाले होते तो क्या आप जवाब दे देते?

श्री महावीर प्रसाद: सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैंने अभी-अभी कहा है कि अगर ये जानकारी चाहते हैं तो हम इन्हें दे देंगे।

श्री सभापति: आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है।

*587. [The questioner Shri S.P.M. Syed Khan was absent for answer *vide* page 47].

Agricultural labourers

*588. SHRI NAND KISHORE YADAV: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether a study has been done on the increasing unemployment of agricultural labourers in non-seasonal periods;